

[DR. BARUN MUKHERJI]

I would, therefore, urge the Government of India, particularly the hon. Home Minister, to revisit the whole issue and sympathetically take necessary measures to rename Silchar station as Bhasha Saheed Station, Silchar.

Demand to take strict action against foreign companies involved in illegal testing of medicines on the poor, dalits and tribals in the country

डा. राम प्रकाश (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, आज हमारे देश में विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत में औषधि परीक्षण के मामले रोज बढ़ते जा रहे हैं। इन परीक्षणों हेतु दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत 20 प्रतिशत तक सस्ता है। यहां गरीब, अनपढ़, दलित व आदिवासी लोग नियमों की जानकारी न होने के कारण मात्र पांच हजार रुपए में अपने जीवन को खतरे में डाल देते हैं। यहां तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी हस्तक्षेप करते हुए सरकार से कहा है कि इस गोरखधंधे को रोकने के लिए तुरन्त उपाय किए जाएं। भारत में इन गैर-कानूनी व अनैतिक परीक्षणों के कारण गत तीन वर्षों में तकरीबन 1,300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल 22 लोगों को मुजावजा दिया गया। दवाओं के परीक्षण आवश्यक हैं, परन्तु उनके लिए जो नियम हैं, उनका पालन होना चाहिए। यदि यह अनैतिक कारोबार इसी प्रकार चलता रहा, तो एक दिन इस देश में गरीबों के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस गैर-कानूनी व अनैतिक गोरखधंधे को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए।

Demand to take suitable steps to check the problem of brain drain in DRDO

श्री कप्तान सिंह सोलंकी (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, देश के शीर्षस्थ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) में रक्षा वैज्ञानिकों का पलायन एक चिंता का विषय है। बीते पांच सालों में इसके 650 वैज्ञानिकों ने इस्टीफा देकर निजी क्षेत्र की राह पकड़ ली है। आश्चर्यजनक तो यह है कि छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद भी रक्षा वैज्ञानिकों का पलायन लगातारी जारी है। रक्षा मंत्रालय के आंकड़े गवाह हैं कि वर्ष 2007 से लेकर पिछले साल यानी 2011 तक डीआरडीओ की विभिन्न यूनिटों से 649 रक्षा वैज्ञानिकों ने अपने सेवाकाल के बीच में ही इस्टीफा देकर निजी क्षेत्र की नौकरी को तवज्ज्ञह दी है। वर्ष 2007 में 273 रक्षा वैज्ञानिक, 2008 में 162, 2009 में 65, 2010 में 63 तथा 2011 में 86 रक्षा वैज्ञानिक सरकारी नौकरी से पलायन कर चुके हैं। वर्ष 2008 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के सामने आ जाने के बाद भी देश के शीर्ष संगठन से वैज्ञानिकों का पलायन जारी है। 2008 से लेकर 2011 के चार साल में 376 वैज्ञानिक इस्टीफा दे चुके हैं। डीआरडीओ में मौजूदा समय में तकरीबन सात हजार वैज्ञानिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि देश के सर्वोच्च रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में रक्षा वैज्ञानिकों का इस प्रकार से लगातार पलायन हुआ तो देश की रक्षा सम्पदा एवं नीति को काफी नुकसान हो सकता है और सरकार इस मामले की गंभीरता से लेते हुए उचित समाधान निकाले, जिससे इस पलायन को रोका जा सके।

Recent goodwill visit of US Secretary of State to India

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal) : Sir, the recent visit of Ms. Hillary Clinton, the US Secretary of State, to India and particularly to West Bengal is not just a goodwill visit. It will help in strengthening the longstanding ties between India and the USA. The reported desire conveyed during the visit about US investment